मध्यप्रदेश में 'बाढ़ पर्यटन' से उपजे सवाल!

- राजेन्द्र चतुर्वेदी

हाल ही में मंदसौर जिले में 'बाढ़-पर्यटन'करने पहुंचे मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने कहा, 'बाढ़ के कारण स्थिति भयानक है। जनता परेशान है। यह क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम इस पर बाद में बात करेंगे। सरकार से सवाल पूछेंगे, लेकिन पहली प्राथमिकता जनता को राहत देने की है। बाढ़ में जिन लोगों का सब कुछ बह गया, उनकी मदद करना सबका कर्तव्य है।' अतिवर्षा से तबाह हुई फसलों को लेकर भी 'पर्यटन' का दौर चल रहा है। किसानों के जख्मों पर 'मल्हम' लगाने के लिए नेतागण पहुंच रहे हैं।

पहले बात- बाढ़ की। कह सकते हैं - 'बहुत खूब।' पूर्व सीएम ने कितनी 'खूबसूरत' बात कही। उनकी टीम के अन्य नेता भी इसी तरह की 'सुंदर बातें' करते घूम रहे हैं। खैर, सच तो यही है कि पूर्व सीएम 'परिस्थितिनुसार' स्वयं के चेहरे पर 'भाव पैदा' करने में पारंगत हैं। वे 15 साल तक प्रदेश की सत्ता और कोई 13 बरस मुख्यमंत्री रहे - और इस दौरान खूब 'बातें' कीं। अब सत्ता चली गई है, लेकिन बातें करने की आदत तो जा नहीं सकती।

भाई साहब, अगर प्रदेश में बाढ़ ने हाहाकार मचाया है, तो- पहला जवाब तो आपको ही देना चाहिए, न कि वर्तमान सरकार को - जो अभी करीब नौ महीने पहले सत्ता में आई है। अपने 15 साल के कार्यकाल में आपने उचित अगर रणनीति बनाकर काम किया होता, तो मध्यप्रदेश को बाढ़ से हमेशा-हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया होता है। 15 साल का समय बहुत होता है। इतने लंबे कालखंड में कुछ भी किया जा सकता है, बशर्ते करने की इच्छाशक्ति हो। बहरहाल, आपने जो किया, उसकी चर्चा बाद में।

बेशक, बाढ़ प्राकृतिक आपदा होती है, लेकिन प्रकृति के प्रवाह में इंसान का जरूरत से ज्यादा दखल आपदा को विकराल बना देता है। इंसान जब प्रकृति को काबू में करने की कोशिश करता है, तो वह अपना विकराल रूप दिखाकर, हमें सावधान करने की कोशिश करती है। प्रकृति चेतावनी देती है कि मनुष्य जिस विज्ञान के भरोसे है- वह प्रकृति के सामने बहुत बौना है।

क्या यह बताने की जरूरत है कि आज प्रकृति के प्रवाह में इंसान का दखल किस हद तक बढ़ गया है? नदियों पर ऊंचे-ऊंचे बांध बना दिए गए हैं। बांधों की अंदरूनी सफाई की भी कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे उनमें गाद भर गया है और इसीलिए उनकी जलभराव क्षमता कम हो गई है। बाढ़ के साथ मिट्टी नदियों-नालों में पहुंचती है और उनकी गहराई को उथला कर देती है, जिससे नदियों का पाट चौड़ा हो जाता है। इन नदियों में जब बाढ़ आती है, तो उनकी जलधारा ज्यादा चौड़ी हो जाती है, और ज्यादा तबाही मचाती है। बाढ़ के पानी में मिट्टी इसलिए आती है, क्योंकि जंगल साफ हो गए हैं। यह जानने के लिए पर्यावरणविद् होने की जरूरत नहीं है कि केवल वृक्ष ही मिट्टी के बहाव को रोक पाते हैं। जब वृक्ष नहीं होंगे, तो मिट्टी तो बहेगी ही। नदियों और नालों से जब वैध-अवैध तरीकों से बालू और पत्थरों का उत्खनन होगा, तो नदियों के पाट को चौड़ा होने से कौन रोकेगा?

शहरों-कस्बों की स्थित यह है कि प्राकृतिक जलस्रोतों को समतल करके या तो उन पर इमारतें तान दी गई हैं या फिर वे कचरा डंपिंग की जगह बन गए हैं। यह इसी का नतीजा है कि जब बारिश होती है, तो सड़कों पर बाढ़ आ जाती है। प्रदेश में पिछले 15 सालों में जो सड़कें बनीं, वे बारिश में हर साल उखड़ जाती है। फिर जब उसकी मरम्मत होती है, तो ऊंचाई बढ़ जाती है। सड़क ऊंची होगी और मकान नीचा, तो सड़क का पानी मकान में ही भरेगा।

याद नहीं आता कि प्रदेश की सत्ता में 15 साल रही सरकार ने किसी बांध, किसी नदी की गाद की सफाई कराई हो। भोपाल की बड़ी झील के जलभराव क्षेत्र में ऊंची-ऊंची इमारतें आज नहीं बन गई हैं। छोटी झील आज

प्रदूषित नहीं हुई है। शहर के ज्यादातर तालाब कचरा डंपिंग के स्थान पिछले नौ महीने में नहीं बने हैं। पिछले 15 सालों में अगर प्रदेश का 30 प्रतिशत वन क्षेत्र कम हो गया है, तो इसका जवाबदेह कौन है? प्रदेश की जनता कैसे भूल सकती है कि खनन माफिया, पुलिस-प्रशासन की टीमों पर हमले कराता रहा है? जिस प्रदेश में एक आईपीएस अफसर को टैक्टर से कुचलकर मार दिया गया था, वह मध्यप्रदेश ही है।

इस स्थिति में काम की बात की जाए, तो ज्यादा ठीक रहेगा। जनता को बताया जाए कि पिछले 15 सालों में बाढ़ की आपदा से निपटने के लिए कौन सा तंत्र विकसित किया गया? क्या बाढ़ग्रस्त इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई की कोई व्यवस्था पिछले 15 सालों में बनाई गई? क्या कोई ऐसा ढांचा बनाया गया, जो बाढ़ का कहर खत्म होने के बाद सक्रिय हो जाए और लोगों को महामारी की चपेट में न आने दे? दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन सभी सवालों का जवाब 'न' है।

जल, जंगल, जमीन के संरक्षण के लिए कुछ किया होता, तो बाढ़ जैसी आपदा का असर उतना मारक नहीं होता, जितना आज है। इसके बावजूद सबसे ज्यादा सुकून की बात यह है कि जनहानि नहीं हुई। जब महज और महज 'लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड' भर में पौधारोपण का 'रिकार्ड' दर्ज कराना 'मकसद' होगा तब ऐसे प्रयास मात्र रस्मादायगी तक ही सीमित होकर रह जायेंगे। जोर पौधों को पालने-पोसने पर नहीं, उनकी गिनती बढ़ाने पर होगा, तो बात नहीं बनेगी रिकॉर्ड बनाने के लिए रोपे गए पौधे लहलहाने से तो रहे।

आप और आपकी टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों और फसलें चौपट हो जोन वाले क्षेत्रों में जायजा लेने के लिए यहां-वहां 'भटकती' फिर रही है, उस पर विराम लगाइए। जब आप लोग कहीं पहुंचते हैं, तो प्रशासनिक अमले का काम कुछ ज्यादा कठिन होता जाता है। जिन अधिकारियों-कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों को बाढ़ और अतिप्रभावित क्षेत्रों के लोगों की मदद में जुटा होना चाहिए, उस समय प्रोटोकॉल के मद्देनजर वे आपके स्वागत-सत्कार, देख-रेख और 'पर्यटन' के काम में मजबूरीवश मदद के लिए जुटे होते हैं। इस आपदाकाल में प्रशासन की दिक्कतें बढ़ाने से बचें। अतिबारिश और बाढ़ अथवा ऐसी अन्य आपदा के पलों को नेताओं द्वारा अपनी राजनीति चमकाने के अवसर में बदलने की नीति कम से कम जनता को रास नहीं आती है। (प्रस्तुति: मनुज फीचर सर्विस)

नोट: मनुज फीचर सर्विस में छपे लेखों के विचार लेखक के अपने हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। यहां प्रकाशित सामग्री का उपयोग गैर व्यावसायिक कार्यों के लिए करने हेतु किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मनुज फीचर सर्विस का उल्लेख अवश्य करें।